REVIEW ARTICLE Bhartiya Krishi Anusandhan Patrika, Volume 38 Issue 3: 203-209 (September 2023)

डेरी उद्योग एक आत्मनिर्भर भारत की पहचान (भारत में डेरी उद्योग का विकास): एक समीक्षा

अक्षय रमानी[1], राजेश देशमुख[1], रमन सेठ[1], कमल गांधी[1], राजन शर्मा[1]

सारांश

डेरी उद्योग आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। 1965 में दिवंगत प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा शुरू की गई श्वेत क्रांति के दिनों से भारत में डेरी क्षेत्र ने एक लंबा सफर तय किया है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को लागू करने के लिए 1965 में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य था भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनायें। 2021–22 में 221.06 मिलियन टन दूध उत्पादन के साथ आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। भारत में डेरी उद्योग न केवल लाखों किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश की जीडीपी में 4% से अधिक का योगदान देता है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। भारत में डेरी क्षेत्र एक बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक बड़ी शाकाहारी आबादी के लिए पशु प्रोटीन का स्रोत प्रदान करता है।

मुख्य शब्दः डेरी उद्योग, विकास, दूध।

Development of Dairy Industry- An Identity of India's Self-reliant: A Review

Akshay Ramani[1], Rajesh Deshmukh[1], Raman Seth[1], Kamal Gandhi[1], Rajan Sharma[1] **10.18805/BKAP625**

ABSTRACT

Dairy industry is a self-reliant India's identity. The dairy sector in India has come a long way since the days of the White Revolution launched by late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri in 1965. The National Dairy Development Board (NDDB) was established in 1965 to implement the Operation Flood program which aimed to make India self-sufficient in milk production. Today, India is the world's largest milk producer, with milk production of about 221.06 million tonnes in 2021-2022. The dairy industry in India is not only an important source of income for millions of farmers and rural households, but it also plays a vital role in the country's economy. It contributes to more than 4% of the country's GDP and provides employment opportunities to millions of people, both directly and indirectly. The dairy sector in India also plays a critical role in ensuring food security for a large population and provides a source of animal protein for a large vegetarian population.

Key words: Dairy industry, Development, Milk.

भारत में डेरी क्षेत्र का विकास और ऑपरेशन फ्लड की शुरूआत के बाद से डेरी सहकारी समितियों द्वारा निभाई गई शानदार भूमिका आजादी के बाद देश की उल्लेखनीय विकास गाथा का एक अभिन्न हिस्सा है। आज भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो वैश्विक दूध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। डेरी उद्योग देश के कुल आर्थिक उत्पादन के 5% और 8 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत में डेरी व्यवसाय ने पिछले एक दशक में पर्याप्त वृद्धि का किया है। 2014–2015

[1]Division of Dairy Chemistry, ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal-132 001, Haryana, India.

Corresponding Author: Akshay Ramani, Division of Dairy Chemistry, ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal-132 001, Haryana, India. Email: akshayramani888@gmail.com

How to cite this article: Ramani, A., Deshmukh, R., Seth, R., Gandhi, K. and Sharma, R. (2023). Development of Dairy Industry- An Identity of India's Self-reliant: A Review. Bhartiya Krishi Anusandhan Patrika. 38(3): 203-209. doi:10.18805/BKAP625.

Submitted: 18-01-2023 **Accepted:** 02-06-2023 **Online:** 25-07-2023

में 146.31 मिलियन टन (MT) से 2021–22 में 221.06 MT तक, देश में वार्षिक दूध उत्पादन 5.29% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा, राजस्थान भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है (BAHS, 2022)। जो कुल दूध उत्पादन में लगभग 15.05% का योगदान देता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, और आंध्र प्रदेश क्रमशः 14.93%, 8.7%, 7.56% और 6.97% हैं (BAHS, 2022) (ग्राफ 1)।

गाय, भैंस और बकरियों द्वारा किए गए दूध उत्पादन में योगदान का प्रतिशत ग्राफ 2 में प्रदर्शित किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, कुल दूध उत्पादन में देशी भैंसों का हिस्सा लगभग 31.58% है। क्रॉसब्रेड गाय कुल दूध उत्पादन का 29.91% के लिए जवाबदार है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में स्वदेशी गाय का हिस्सा 10.35% है, जबकि गैर–वर्णित गाय 9.82% और गैर–वर्णित भैंस देश के कुल दूध उत्पादन का 13.49% के लिए जवाबदेह हैं। क्रॉसब्रेड गाय कुल दूध उत्पादन का 29.91% है। बकरियों से उत्पादित दूध देश भर में कुल दूध उत्पादन का 2.93% है। कुल दूध उत्पादन का एक हिस्सा (1.92%) विदेशी गायों से आता है। देशी, विदेशी एवं संकर नस्लों की गाय, भैंस, बकरी के माध्यम से राज्यवार दुग्ध उत्पादन 2021–22 का वर्णन तालिका 1 में किया गया है।

भारत में डेरी उद्योग का इतिहास

1950 और 1960 के दशक में परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। भारत एक ऐसा देश था जो दूध की कमी से पीड़ित था जो पूरी तरह से आयात पर निर्भर था और देश की वार्षिक उत्पादन वृद्धि कई वर्षों से नकारात्मक रही थी (Khan and Prashari, 2014)। स्वतंत्रता के बाद पहले दशक के दौरान दूध उत्पादन में वार्षिक चक्रवृद्धि दर 1.64% थी, लेकिन 1960 के दशक के दौरान यह घटकर 1.15% रह गई (Kunte and Patankar, 2015)।

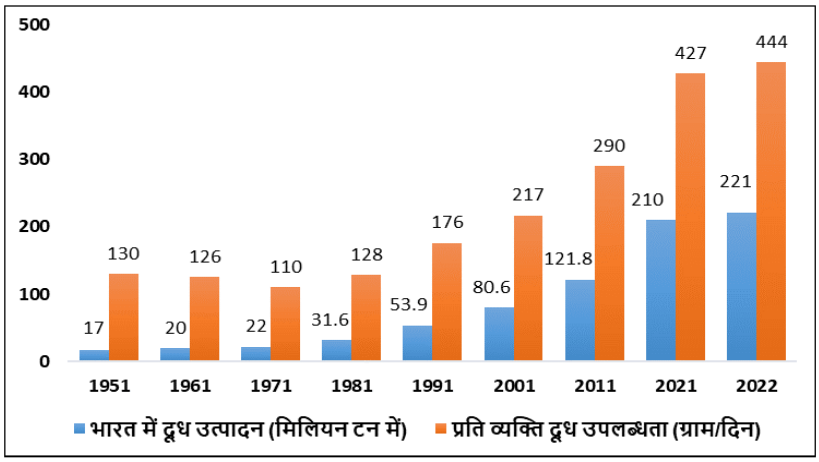

ग्राफ 1: भारत में दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता (BAHS, 2022)।

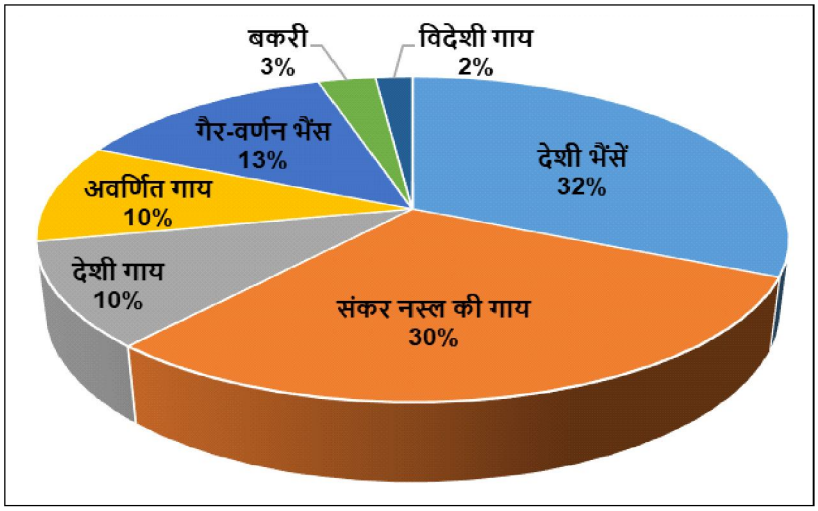

ग्राफ 2: गाय, भैंस और बकरियों का कुल दूध उत्पादन में योगदान।

यह गिरावट उस दशक के दौरान हुई जो स्वतंत्रता के वर्ष के बाद आई थी। वर्ष 1950–1951 में देश भर में दूध की औसत दैनिक खपत प्रति व्यक्ति मात्र 124 ग्राम थी (Drace, 1970)। यह आंकड़ा 1970 तक गिरकर 107 ग्राम प्रति दिन हो गया था, जिससे यह दुनिया में सबसे कम और न्यूनतम अनुशंसित पोषण मानकों से काफी नीचे था। भारत में डेरी उद्योग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। दुनिया में पशु की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद, देश में हर साल 21 मिलियन टन से भी कम दूध का उत्पादन होता है (Delgado *et al*., 2001; Rajendran and Mohanty, 2004)।

1964 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री की गुजरात के आणंद जिले की यात्रा के बाद, 1965 में देश भर में डेरी सहकारी समितियों के ''आनंद पैटर्न'' के निर्माण का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) बनाया गया था (Kunte and Patankar, 2015)। डॉ वर्गीज कुरियन, जिन्हें पूरे भारत में ''श्वेत क्रांति के जनक'' के रूप में जाना जाता है। वे राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (NDDB) के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया (NDDB, 2022)। डॉ. कुरियन ने अपनी टीम के साथ परियोजना के शुभारंभ पर काम शुरू किया। इस परियोजना में पूरे देश में स्थित दूधशाला में आनंद–पैटर्न सहकारी समितियों की स्थापना की कल्पना की गई थी। इन दूधशालाओं से दूध सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित और खरीदे जाने वाले दूध को शहरों तक पहुंचाया जाएगा।

ऑपरेशन फ्लड

ऑपरेशन फ्लड (ओएफ) कार्यक्रम के माध्यम से जिसे चरणों में लागू किया जाना था। ''आनंद पैटर्न'' अनिवार्य रूप से एक सहकारी संरचना थी जिसमें ग्राम–स्तरीय डेरी सहकारी समितियाँ (DCS) शामिल थीं, जो जिला–स्तरीय यूनियनों को बढ़ावा देती हैं, जो बदले में राज्य–स्तरीय विपणन संघ को बढ़ावा देती हैं (Khan and Prashari, 2014)। 1970 में एनडीडीबी ने पूरे भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से आनंद पैटर्न सहकारी समितियों को पूरे भारत में फैला दिया गया (Candler and Kumar, 1998)।

1. चरण I: (1970–1980) को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा दान किए गए स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल की बिक्री से वित्तपोषित किया गया था (Doornbos *et al*., 1990)।

2. चरण II: (1981–1985) में दूधशालाओं की संख्या 18 से बढ़ाकर 136 की गईय शहरी बाजारों ने दूध के दुकान को बढ़ाकर 290 कर दिया। 1985 के अंत तक, 42,50,000 दूध उत्पादकों के साथ 43,000 ग्रामीण सहकारी समितियों की एक आत्मनिर्भर प्रणाली को स्थापित किया गया (Candler and Kumar, 1998)।

3. चरण III: (1985–1996) ने डेरी सहकारी समितियों को दूध की बढ़ती मात्रा की खरीद और विपणन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विस्तार करने और उसे मजबूत करने में सक्षम बनाया। इस चरण में 30000 नई डेरी सहकारी समितियाँ जोड़ी गईं, जिससे कुल संख्या 73,000 हो गई (Khan and Prashari, 2014)।

ऑपरेशन फ्लड ने राष्ट्रीय दूध ग्रिड के माध्यम से 700 कस्बों और शहरों में उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण दूध पहुंचाने में मदद की। कार्यक्रम ने बिचौलियों की आवश्यकता को दूर करने में भी मदद की, जिससे मौसमी मूल्य भिन्नता कम हो गई। सहकारी संरचना ने दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन और वितरण के पूरे अभ्यास को किसानों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना दिया। इसने आयातित ठोस दूध पर भारत की निर्भरता को भी समाप्त कर दिया। देश न केवल अपनी स्थानीय डेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए सुसज्जित था, बल्कि इसने कई विदेशी देशों को दूध पाउडर का निर्यात भी शुरू कर दिया था। संकरण के कारण दुधारू पशुओं के आनुवंशिक सुधार में भी वृद्धि हुई है। जैसे–जैसे डेरी उद्योग का आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ, लगभग 10 मिलियन किसानों ने ने अपनी आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में डेरी फार्मिंग शुरू की (Kunte and Patankar, 2015)।

1950–1951 के वर्षों में उत्पादित दूध की मात्रा केवल 17 मिलियन टन (MT) थी (Singh and Datta, 2010)। 1968–1969 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत से पहले, दूध का उत्पादन केवल 21.2 मीट्रिक टन था। हालाँकि, 1979–1980 तक, यह संख्या बढ़कर 30.4 MT हो गई थी, और 1989–1990 तक यह बढ़कर 51.4 MT हो गई थी (Dixit, 2014)। वर्तमान में, यह वर्ष 2021–22 में 221.06 मिलियन टन है, जो ग्राफ 2 में दिखाया गया है (BAHS, 2022)। पूरे विश्व में, दूध उत्पादन प्रति वर्ष दो प्रतिशत की गति से बढ़ रहा है, लेकिन भारत में यह दर प्रति वर्ष छह प्रतिशत से अधिक है। दुनिया के बाकी हिस्सों के औसत की तुलना में भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता काफी अधिक है। देश में दूध की खपत 1970 में प्रति व्यक्ति 107 ग्राम के निचले स्तर से बढ़कर 2021–22 में 444 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई (ग्राफ 2), जो दुनिया भर में दूध की औसत खपत से अधिक है, जो 2021 के दौरान प्रति दिन 322 ग्राम है (BAHS, 2022)। यह वृद्धि तीन दशकों (1980, 1990 और 2000 के दशक) के दौरान हुआ (Anonymous, 2022g)।

तालिका 1: 2021–22 के दौरान राज्यवार दुग्ध उत्पादन (टन में)।

राज्य	गाय			भैंस		बकरी
	स्वदेशी	विदेशी	क्रॉसब्रेड	स्वदेशी	गैर–वर्णनात्मक	
आंध्र प्रदेश	741.08	315.93	305.21	7980.92	7980.92	4.15
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	34.53	0.55	0.55	0.00
असम	524.78	0.00	0.00	129.13	129.13	18.37
बिहार	0.00	435.87	3526.32	4217.67	4217.67	142.32
छत्तीसगढ	453.04	41.11	633.75	176.39	176.39	72.93
गोवा	0.00	0.00	49.70	0.00	0.00	0.56
गुजरात	847.52	0.00	2020.59	5764.14	5764.14	339.18
हरयाणा	146.61	237.45	396.16	7914.16	7914.16	55.82
हिमाचल प्रदेश	113.25	39.86	4.08	274.23	274.23	51.22
जम्मू और कश्मीर	384.99	87.54	10.24	174.13	174.13	73.47
झारखंड	607.10	108.31	661.46	279.12	279.12	190.26
कर्नाटक	684.36	0.00	1043.28	1515.20	1515.20	55.67
केरल	24.96	0.00	4.37	9.39	9.39	123.27
मध्य प्रदेश	5479.15	229.96	1087.30	3174.56	3174.56	961.71
महाराष्ट्र	442.7	458.81	7196.64	2688.71	2688.71	327.19
मणिपुर	31.26	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नगालैंड	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
ओडिशा	715.26	0.00	86.80	20.83	20.83	4.27
पंजाब	68.19	1173.09	379.37	7506.65	7506.65	91.69
राजस्थान	4144.62	0.00	5077.46	8635.89	8635.89	2319.94
सिक्किम	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	499.10	0.00	117.02	80.46	80.46	117.16
तेलंगाना	650.00	183.66	189.75	2910.05	2910.05	6.25
त्रिपुरा	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
उतार प्रदेश	1977.36	875.82	3660.95	15731.19	15731.19	1293.92
उत्तराखंड	26.62	52.11	285.60	451.29	451.29	51.26
पश्चिम बंगाल	2390.50	0.00	1341.56	153.47	153.47	151.99
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
चंडीगढ़	1.33	5.87	0.03	23.09	23.09	0.27
दमन और दीव और	0.09	0.53	0.50	0.00	0.00	0.00
लद्दाख	1.02	0.00	2.75	0.12	0.12	0.11
दिल्ली	—	—	—	—	—	—
लक्षद्वीप	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
पुदुचेरी	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल दुग्ध उत्पादन	21712.33	4250.62	21321.97	69812.24	29813.95	6468.60

ऑपरेशन फ्लड के बाद, भारत में डेरी और पशुपालन क्षेत्र बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों के लिए आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में उभरा, जिनमें से अधिकांश भूमिहीन किसान, छोटे किसान या सीमांत किसान थे। आज भारत इस बात से गर्व कर सकता है कि पिछले ढाई दशकों में यह दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश रहा है।

डेरी उत्पादों का निर्यात

भारत में डेरी उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो लाखों किसानों को आजीविका प्रदान करता है और निर्यात के माध्यम से महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न करता है। हाल के वर्षों में, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय डेरी उत्पादों, जैसे घी, पनीर और दही की मांग बढ़ी है। इससे इन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश भारतीय डेरी उत्पादों के प्रमुख आयातक हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत के डेरी उत्पादों के निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। भारत ने 2021–22 में दुनिया के बाकी हिस्सों में 108,711 मीट्रिक टन डेरी उत्पादों का निर्यात किया, जिससे कुल रु 2,928.79 करोड़ (US$ 391.59 मिलियन) (Anonymous, 2022) (ग्राफ 3)।

हालांकि, विदेशों द्वारा निर्धारित सख्त नियमों और गुणवत्ता मानकों के कारण भारतीय डेरी उत्पादों का निर्यात करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। डेरी उत्पादों का निर्यात करने के लिए, भारतीय निर्माताओं को इन नियमों का पालन करना चाहिए और आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारतीय डेरी उद्योग को यह सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता और स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखना चाहिए कि उनके द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पाद उपभोग के लिए सुरक्षित हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, भारत सरकार डेरी उत्पादों के निर्यात को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, उद्योग के लिए महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न करने और रोजगार सृजित करने की क्षमता को पहचानते हुए। हाल के वर्षों में, डेरी उद्योग के विकास का समर्थन करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय डेरी उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में डेरी उद्योग का महत्व

कई विभिन्न कारकों के कारण, भारत का डेरी उद्योग देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्षेत्र के रूप में, यह 80 मिलियन से अधिक ग्रामीण परिवारों के रोजगार के लिए जिम्मेदार है, जिनमें से अधिकांश भूमिहीन लोगों के साथ–साथ छोटे और सीमांत किसान हैं (Khan and Prashari, 2014)। सहकारी समितियों ने न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाया है, बल्कि उन्होंने लोगों को लिंग, जाति, धार्मिक परंपरा और सामुदायिक मानदंडों की बाधाओं से भी मुक्त किया है। इस देश में डेरी उद्योग में अधिकांश श्रमिक महिला विशेष रूप से उत्पादक हैं। उद्योग विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों का एक महत्वपूर्ण प्रदाता है और यह महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

डेरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने 2001 से 1 जून को विश्व दूध दिवस के रूप में नामित किया है। इस उत्सव का उद्देश्य दुनिया भर में भोजन के रूप में दूध के

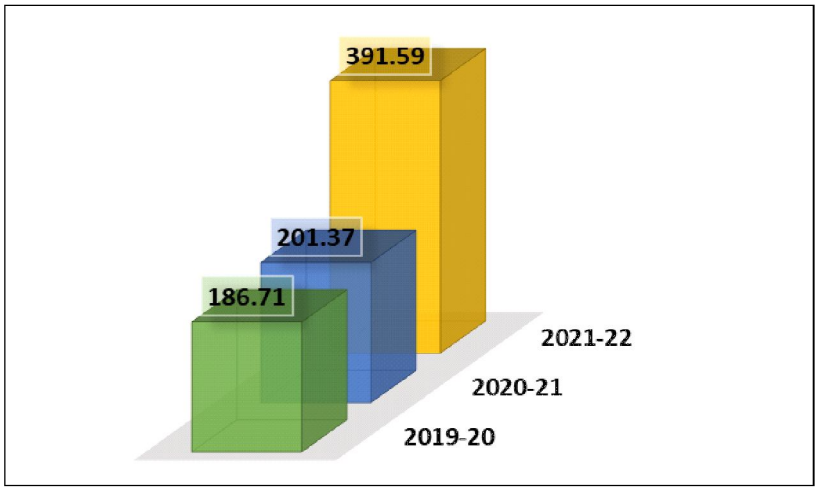

ग्राफ 3: भारत से डेरी उत्पादों का निर्यात (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)।

महत्व को पहचानना और डेरी उद्योग का सम्मान करना है। विश्व दूध दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। 26 नवंबर को, जो डॉ. वर्गीज कुरियन का जन्मदिन भी होता है, भारत देश राष्ट्रीय दूध दिवस मनाता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय दूध दिवस के अवसर पर, भारत सरकार सहकारी समितियों और दूध उत्पादक कंपनियों को वैज्ञानिक तरीके से प्रेरित करने के साथ–साथ किसानों को दूध पशुओं की स्वदेशी नस्लों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान कर रही है। 2022 में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार डॉ. बाबू राजेंद्र प्रसाद को केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेरी राज्य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, जीकेवीके कैंपस, बेंगलुरु, कर्नाटक में राष्ट्रीय दूध दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया गया।

✓डेरी उद्योग के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPDD)

डेरी विकास के लिए राष्ट्रीय नीति (NPDD) मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले दूध के उत्पादन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और सुधार के साथ–साथ राज्य एजेंसियों द्वारा दूध और दूध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है। राज्य सहकारी डेरी संघ और जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (NPDD, 2022)।

✓राष्ट्रीय डेरी योजना (चरण–I) (NDP–1)

कार्यक्रम के लक्षित परिणामों में से अधिकांश का एहसास हो गया है, विशेष रूप से नस्ल विकास और सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देश भर में दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान दूध उत्पादन में 6% से अधिक की वृद्धि हुई है। NDP-I कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च–आनुवंशिक सांडों की संख्या में वृद्धि करके नस्ल की गुणवत्ता में सुधार करना था, साथ ही सहकारी संगठन के दायरे का विस्तार करना था। कार्यक्रम के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त 55,000 बस्तियों को शामिल करने के लिए दूध संग्रह का विस्तार किया गया (DEDS, 2022)।

✓डेरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS)

2010 में शुरू की गई, डेरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जो वाणिज्यिक, सहकारी, शहरी और ग्रामीण बैंकों से ऋण के साथ व्यावसायिक रूप से बैंक योग्य परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है (NAIP, 2022)। ''सामान्य'' श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25% और ''अनुसूचित जाति'' और ''अनुसूचित जनजाति'' श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 33.33% बैक–एंडेड सब्सिडी (NAIP, 2022)।

✓पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)

सरकार ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में कुल 15,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है (AHIDF, 2022)। देश में डेरी उत्पादन और प्रसंस्करण सुविधाएं बढ़ाने की सरकार की योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए समर्पित कोष की घोषणा प्रशासन के लिए पहली है।

✓राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP)

देश की सरकार ने सितंबर 2019 में राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP) की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य देश के 600 जिलों में से प्रत्येक में 20,000 गायों में कृत्रिम शुक्राणु प्रत्यारोपित करना है (NAIP, 2022)। यह अपनी तरह के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है, और यह नस्लों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भविष्य में, यह पहल भारत के उन सभी 600 जिलों में फैल जाएगी जहां प्रजनन योग्य गोजातीय आबादी है।

✓Covid–19 के दौरान सहायता

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, पशुपालन और डेरी विभाग (डीएएचडी) ने ''वर्किंग कैपिटल लोन पर ब्याज सबवेंशन'' नामक एक पहल को अपनी मंजूरी दे दी है। यह पहल दुग्ध संघों, दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों जैसे उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस पहल के लिए कुल परिव्यय एक सौ करोड़ रुपये है।

गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF/Amul), कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन (KMF/नंदिनी), तमिलनाडु कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन (आविन), और अन्य राज्य डेरी फेडरेशन, मदर डेरी जैसे डेरी सहकारी समितियों जैसे उत्पादक स्वामित्व वाले संगठन और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को उपभोक्ताओं को दूध की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनी आपूर्ति श्रृंखला को संशोधित करना पड़ा। इसके अलावा, उन्हें सामाजिक दूरी जैसे विभिन्न कदमों को सुनिश्चित करना था। बहुसंख्यक सहकारी समितियों ने अपने अधिग्रहण की सामान्य मात्रा की

तुलना में लगभग 8–10% अधिक दूध प्राप्त किया। कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान, सहकारी समितियां यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थीं कि किसानों को दूध खरीद के लिए तेजी से भुगतान प्राप्त हो (Madhavan *et al*., 2020)।

निष्कर्ष

ऑपरेशन फ्लड के बाद, भारत में कई ग्रामीण परिवारों ने अपनी आय के मुख्य स्रोत के रूप में डेरी और पशुपालन उद्योगों की ओर रुख किया। लगभग 25 वर्षों तक, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश रहा है। इसने पिछले 20 वर्षों में दोगुना दूध का उत्पादन किया है। डेरी उद्योग ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विस्तार में बहुत मदद की है। राष्ट्रीय डेरी योजना के साथ–साथ जन धन योजना और स्टार्ट–अप इंडिया पहल जैसे सामान्य सशक्तिकरण कार्यक्रम, सरकार के उन उपायों में से थे, जिन्होंने डेरी खेती के लिए बुनियादी ढांचे में मदद की। प्रधान मंत्री मोदी के आत्मानबीर भारत एजेंडे के तहत, पशुपालन और डेरी क्षेत्रों में पिछले आठ वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, और उनकी प्रगति स्वतंत्रता का एक प्रभावशाली उदाहरण है।

संदर्भ

NDDB (2022). National Dairy Development Board (NDDB) https://www.nddb.coop/information/stats/milkprodstate.

AHIDF (2022). Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) https://dahd.nic.in/schemes/programmes/ahidf.

DEDS (2022). Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS) https://www.nabard.org/content. aspx?id=591.

NPDD (2022). National Programme for Dairy Development (NPDD) https://dahd.nic.in/schemes/programmes/npdd.

NAIP (2022). Nationwide Artificial Insemination Programme (NAIP) https://nadrsapps.gov.in/Krishi Kalian/AI Login.aspx.

Department of Animal Husbandry and Dairying https://dahd.nic.in/.

Anonymous (2022). Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying https://pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NoteId=151137andModuleId%20=%202.

BAHS (2022). Basic Animal Husbandry Statistics, Government of India Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, 29-49. https://dahd.nic.in/sites/default/filess/updatedBAHS2022.pdf.

Candler, Wilfred and Kumar, N. (1998). India: The Dairy Revolution: The Impact of Dairy Development in India and the World Bank's Contribution. World Bank Publications.

Delgado, Christopher *et al*. (2001). Livestock to 2020: The next food revolution. Outlook on Agriculture. 30(1): 27-29.

Dixit, Mukund, R. (2014). Amul-2014. Indian Institute of Management Ahmedabad.

Doornbos, Martin, F. van Dorsten, Manoshi Mitra and Piet Terhal. (1990). Dairy Aid Development-India's Operation Flood. Dairy Aid development-India's Operation Flood.

Draèe, Džemal. (1970). Development Of Agriculture, 1945-1970 (In Yugoslavia). Yugoslav Survey. A Record of Facts and Information. 11(4): 13-40.

Khan, N. and Prashari, A.K. (2014). Development of Indian Dairy and Challenges: An Overview. Journal of International Academic Research For Multidisciplinary. 2(11): 431-437.

Kunte, Bhagyashree, S. and Patankar, S. (2015). A literature review of indian dairy industry. International Journal of Management Research and Reviews 5(6): 341-350.

Madhavan, M.K., Krishnakumar and Karpagam, K. (2020). Performance of dairy industry in India: An Analysis. Journal of Xi'an University of Architecture and Technology. 12(6): 1610-1620.

Rajendran, K. and Samarendu Mohanty. (2004). Dairy Co-Operatives and Milk Marketing in India: Constraints and Opportunities. Journal of Food Distribution Research. 35(856-2016-56967): 34-41.

Singh, Shiv Raj and Datta, K.K. (2010). Understanding Value Addition in Indian Dairy Sector: Some Perspectives. Agricultural Economics Research Review. 23(347-2016-16951): 487-94.